इकाई- 2

2

राज्य एवं राष्ट्र की आय

आय (Income)

हम सभी देखते हैं कि समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है, वह अर्जित सम्पत्ति उसकी आय मानी जाती है । व्यक्ति को प्राप्त होनेवाला आय मौद्रिक (रुपये/पैसे) के रूप में, अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है । अर्जित सम्पत्ति की मौद्रिक अभिव्यक्ति आय में होती है । लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त होती है उसे हम आय के रूप में व्यक्त करते हैं ।

किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय ही सम्पन्नता अथवा विपन्नता का प्रतीक है । आय वह मापदंड है, जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है । देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है । भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली और हरियाणा आय के आधार पर ही समृद्ध माना जाता है, वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर जहाँ बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास के निचली श्रेणी का राज्य माना जाता है । इसी प्रकार विश्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों को समृद्ध मानना और भारत को विकास के निचले पायदान पर आय के आधार पर ही रखा जाता है। यह एक अलग बात है कि विगत वर्षों में विकास के दर के कारण भारत तेजी से समृद्ध देशों की श्रेणी की ओर बढ़ता जा रहा है ।

आय :

जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति की **आय** कहते हैं।

जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भूमि का **पारिश्रमिक 'लगान' के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक 'मजदूरी' के रूप में, पूँजी का पारिश्रमिक 'ब्याज' के रूप में, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक 'वेतन' के रूप में एवं उद्यमी का पारिश्रमिक 'लाभ' या 'हानि' के रूप में ही वह उसके आय को प्रकट करता है ।**

बिहार की आय (Income of Bihar)

बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है, जहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरन्तर मौजूद रही है । देश में निर्धनता अनुपात के आँकड़े योजना आयोग ने मार्च, 2009 में जारी किए हैं । इन आँकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ की 41.4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करती है। बिहार राज्य की प्रतिव्यक्ति आय पूरे देशभर में न्यूनतम है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। कम बचत के कारण पूँजी निर्माण दर कम होता है । कम पूँजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है । ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्यों, जैसे-गोवा, दिल्ली आदि में जहाँ प्रति व्यक्ति आय ऊँचा है, बचत एवं विनियोग अधिक है तथा पूँजी निर्माण दर ऊँचा है, जिसके परिणामस्वरूप हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। **सामान्यतः हम यह जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स (Ragnar Nurkse) ने गरीबी के कुचक्र (Vicious Circle of Poverty) के रूप में व्यक्त किया है।** जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाईश (जन्म) अधिक होता है, फलतः उनकीअगली पीढ़ी अधिक

> **आओ जाने :**
> रैगनर नर्क्स (Ragnar Nurkse) ने गरीबी के कुचक्र की धारणा को बतलाया था। बिहार राज्य भी गरीबी के कुचक्र का शिकार है। जिस कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी पूरे भारत वर्ष में न्यूनतम है।

गरीब हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका **आशय यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है ।**

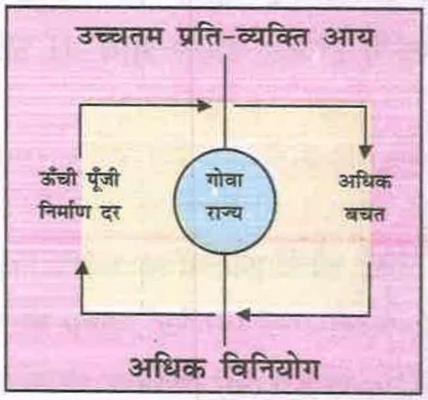

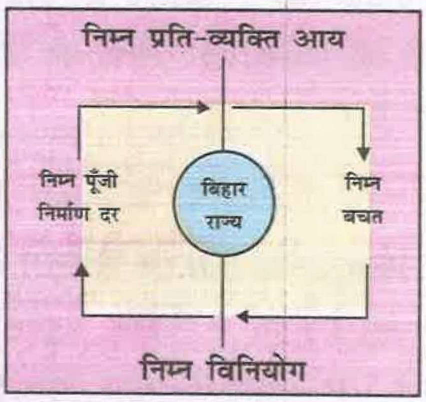

भारत के सभी 28 राज्यों एवं 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है, तथा इस मामले में उसका शीर्ष स्थान विगत पाँच वर्षों से बना हुआ है । देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स (Directorate of Economics and Statistics) कहते हैं, उसके द्वारा 16 सितम्बर, 2008 को जारी किए गए इन आँकड़ों के अनुसार सन् 2006-07 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपए रही है । जबकि देश के केवल 28 राज्यों की चर्चा करें तो इनमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा व दिल्ली का बताया गया है। **निदेशालय के ताजा आँकड़ों में गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपए तथा दिल्ली में यह 50,565 रुपए बताई गई है और तीसरे स्थान पर इस बार हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है।** '2008-09' में बिहार में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (C.S.O.) के अनुसार (11.03) प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर है जो गुजरात (11.05) प्रतिशत के बाद दूसरा है । इस तरह अब बिहार भी पिछड़ापन का चोला त्याग कर विकास की ओर उन्मुख है ।

> **आओ जाने :**
>
> निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन् 2008-09 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपए है । जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सन् 2005-06 में 6,610 रुपए है । बिहार के कुल 38 जिलों में, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय-पटना एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय-शिवहर जिले का है ।

राष्ट्रीय आय (National Income)

अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू है । किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय ही है । जहाँ राष्ट्र की सम्पूर्ण आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के सम्यक् प्रयास से होता है । प्रत्येक साधन की भागेदारी उत्पादन की क्रिया में होती है, फलतः उत्पादित की हुई वस्तुओं से प्राप्त आय का सभी साधनों के बीच में वितरित किया जाता है । अर्थशास्त्र में वितरण (Distrubution) की धारणा राष्ट्रीय आय के आँकलन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न साधनों के भागीदारी में हिस्सा लेने को कहते हैं । वास्तव में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है, और राष्ट्रीय आय को पुनः इन साधनों के बीच वितरित कर दिया जाता है । अब हम राष्ट्रीय आय का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे ।

> **आओ जाने :**
>
> राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है ।
>
> दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को **राष्ट्रीय आय (National Income)** कहा जाता है ।

जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह से प्रक्षेत्र (Area) का निर्माण होता है, प्रक्षेत्रों के समूह से राज्य एवं राज्यों के समूह से देश का निर्माण होता है, उसी प्रकार श्रम एवं पूँजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के उपयोग से जो भौतिक (जिसे मूल्य के रूप में आँका जाता है) और अभौतिक (ऐसी सेवाएँ जो अदृश्य रूप से संसाधनों की वृद्धि करता है) के कुल मूल्य को ही **राष्ट्रीय आय** कहते हैं ।

बच्चों आपने देखा होगा कि प्रायः गाँवों और शहरों में खेत और कल-कारख़ानों के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उसी तरह शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी-पदाधिकारी एवं समाज के अन्य वर्ग के लोग अपनी सेवाओं से राष्ट्र को सुसम्पन्न करते हैं, इस तरह खेत-खलिहानों से उत्पन्न तथा ज्ञान एवं दक्षता से किए गए उत्पादनों को **राष्ट्रीय**

आय कहेंगे । जब इन सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप से आँकलन किया जाता है, तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय (Net National Income) कहते हैं । अर्थशास्त्र में कुल उत्पाद और शुद्ध उत्पाद दोनों ही अवधारणाओं का अपना ही महत्त्व है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे ।

प्रो० अलफ्रेड मार्शल (Prof. Alfered Marshall) के अनुसार "किसी देश की श्रम एवं पूँजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे **राष्ट्रीय आय** कहते हैं।" (The labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds is called National Income.)

जहाँ प्रो० मार्शल की परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत हम उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को लेते हैं, जिनका उत्पादन प्राय: एक साल के अन्तर्गत श्रम एवं पूँजी, प्राकृतिक साधनों के सहयोग से करते हैं ।

आओ जानें ।

यदि देश की कुल पूँजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है ।

प्रो० पीगू (Prof. Pigou) ने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है।

"राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है ।" (National dividend is that part of the objective income of the community, including of course income derived from aborad, which can be measured in money.)

एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **प्रो० फिशर** (Prof. Fisher) ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कहा है कि "वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है, जिसका उस वर्ष के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है ।" (The true National income is that part of annual net produce which is directly consumed during that year.)

तीसा के भयानक आर्थिक मंदी(Great Depression of Thises 1929-33) से उबारने के नियामक **प्रो० केन्स** (Prof. Keynes) ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नये सिरे से विचार किया है । इनके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है।

> **आओ जाने :**
>
> भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) राष्ट्रीय आय के आँकलन के लिए उत्तरदायी है । इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है ।

फार्मूले के रूप में,

$$Y = C + I$$

जहाँ, Y = राष्ट्रीय आय (National Income)

C = उपभोग व्यय (Consumption Expenditure)

I = विनियोग (Investment)

अब हमें राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करना चाहिए जिससे यह पता चले कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किन-किन प्रकारों की आयों की व्याख्या करते हैं । राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय आय की धारणा

1. सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)
2. कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product)
3. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product)

1. **सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)** – किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) कहा जाता है । (The total quantity of goods and services produced in an economy in a given year is called Gross Domestic Product.)

सकल घरेलू उत्पाद :

एक देश की सीमा के अन्दर किसी भी दी गई समयावधि, प्राय: एक वर्ष (लेखा वर्ष) में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) कहा जाता है ।

2. **कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product)**– किसी देश में एक साल के अन्तर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) कहते हैं । यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) तथा सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में अन्तर है ।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है ।

3. **शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product)**– कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है । अत: कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (NNP) कहलाता है। उत्पादन के बीच इसी का वितरण किया जाता है । कुल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) में से कच्चे माल की कीमत, पूँजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसे 'शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन' (NNP) कहते हैं ।

भारत का राष्ट्रीय आय-ऐतिहासिक परिवेश

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे, भारत में सबसे पहले सन् 1868 ई० में **दादा भाई नौरोजी** (Dadabhai

Naoroji) ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था । उन्होंने अपनी पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' में प्रति-व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपए बताया । इसके बाद अनैक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। **प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Dr. V. K. R. V. Rao के द्वारा 1925-29** के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आँकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ई० में **प्रो0 पी0 सी0 महालनोबिस** (P.C. Mahalanobise) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इसमें सन् 1948-49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई तथा प्रति-व्यक्ति आय 246.9 रुपए बताई गई । सन् 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने **केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन** (Central Statistical Organisation) की स्थापना की । यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आँकड़े प्रकाशित करती है, राष्ट्रीय आंय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है ।

प्रति-व्यक्ति आय (Per Capita Income)

भारत जैसे बड़े देश में, जहाँ जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है । यहाँ प्रति-व्यक्ति आय कम है, अशिक्षा का स्तर ज्यादा है एवं भाषा, जीवन शैली और संस्कृति की बहुतायत है । इस बात का अहसास निरन्तर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक-सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपनी **प्रति-व्यक्ति**

प्रति व्यक्ति आय :

राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे **प्रति-व्यक्ति आय** कहते हैं । इसका आकलन निम्न प्रकार से की जाती है :

$$\text{प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय (National Income)}}{\text{देश की कुल जनसंख्या (Total Population of the Country)}}$$

आओ जाने :

भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है तथा प्रति-व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report-2009) के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति-व्यक्ति आय 950 डॉलर था। जहाँ भारत की प्रति-व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति-व्यक्ति आय का लगभग 1/48 है। इसी प्रकार हम विश्व के कुछ देशों के प्रति व्यक्ति आय को निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं।

अमेरिका का प्रति व्यति आय = 46,040 डॉलर
इंगलैंड " " " = 42,740 डॉलर
चीन " " " = 2,360 डॉलर
बंग्लादेश " " " = 870 डॉलर

आय में वृद्धि करें। ऐसा करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, तथा अपना **जीवन-स्तर** (standard of living) ऊँचा कर सकते हैं।

यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कायापलट के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, पर जनसंख्या में भारी वृद्धि तथा अन्य व्यवसायों में उस गति से विकास न होने के कारण विगत् वर्षों में भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता गया है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में हुए सुधार, विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे गुणात्मक विकास के पश्चात् भी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस कारण स्वभावत: यह बेरोजगारी प्रति-व्यक्ति आय को कम करके गरीबी को बढ़ावा देती है। ठीक इसी परिपेक्ष्य में इस अतिरिक्त श्रमशक्ति के बोझ को कम करके और उसे गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके कृषि-उद्योग, बेरोजगारी उन्मूलन और राष्ट्रीय विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

राष्ट्रीय आय की गणना (Measurement of National Income)

जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का ही परिणाम है। उत्पादन प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। इस अर्जित आय के स्वामी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग करते हैं। माँग की यह वृद्धि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक क्रिया का चक्रीय रूप पूरा हो जाता है।

इस कथन को निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।

उत्पादन → आय सृजन —माँग→ व्यय → पुनः उत्पादन वृद्धि प्रेरणा

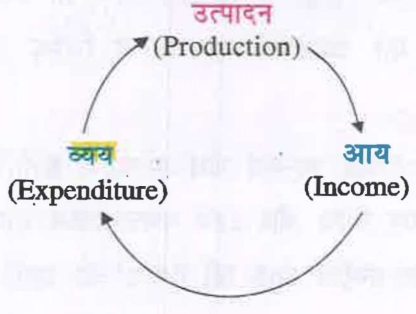

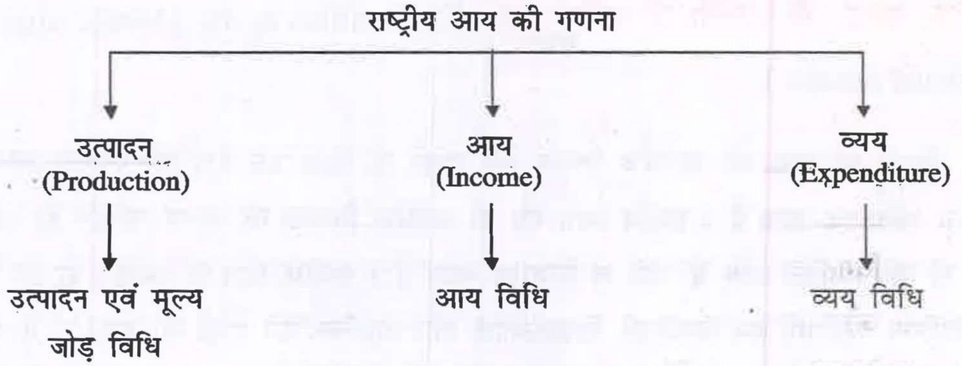

राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है । चूँकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उसे **उत्पादन गणना विधि** (Census of Production Method) कहते हैं। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को **आय गणना विधि** (Census of Income Method) कहा जाता है । प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है, राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि (Census of Expenditure Method) कहते हैं । हम देखते हैं कि उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य

> **आओ जाने :**
> राष्ट्रीय आय राष्ट्र के आर्थिक स्थिति के आँकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है ।

विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को **मूल्य योग विधि (Census of Value Added Method)** कहते हैं। अन्त में व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, व्यवसायिक आधार पर की गई गणना को **व्यवसायिक गणना विधि (Census of Occupation Method)** कहते हैं ।

यद्यपि राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त पाँच तरीकों से होती है, फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र में उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ।

राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ (Difficulties in the Measurement of National Income)

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को ज़ानना आवश्यक होता है । राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सहज मापदंड है, ज़ो उस देश के प्रति-व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है । राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों को हम विकसित, विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं । यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को आँकने का सर्वमान्य माप है । फिर भी हमें व्यवहारिक रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे संक्षिप्त में हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं ।

(i) आँकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई (Difficulty in collecting data)- पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आँकते हैं, और इस आँकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिंनाइयाँ आती हैं । यदि सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति नहीं प्राप्त होती है ।

(ii) दोहरी गणना की सम्भावना (Possibility of double counting)- पूरे राष्ट्र के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आँकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता है । भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी-कभी एक ही आय या उत्पाद को

दो स्थान पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है।

(iii) **मूल्य के मापने में कठिनाई** (Difficulty in measuring the value)- बाजार की स्थिति में प्राय: हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है । वस्तु की कीमत की यह विभिन्नता इसलिए होती है कि विक्रेताओं के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसका यातायात का खर्च, विक्रय व्यवस्था (विज्ञापन) का खर्च और विक्रेताओं की मुनाफे की राशि उसमें जुट जाती है। **उदाहरण**– चीनी का उत्पाद मूल्य कारखानों में कम होता है, जब वह थोक विक्रेताओं के पास जाता है तो उसके मूल्य में बढ़ोत्तरी होती है और अंत में खुदरा विक्रेताओं के पास जाते-जाते उसकी कीमत पूर्व की अपेक्षा काफी अधिक हो जाती है । ऐसी स्थिति में अक्सर विक्रय के दो बिन्दुओं पर अलग-अलग रूप से आँकड़ों को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की भ्रामक स्थिति पैदा होने की संभावना रहती है ।

राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपरोक्त बातों पर ध्यान देने से आँकड़ा स्पष्ट, व्यवहारिक और विश्वसनीय प्राप्त होते हैं । जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के संग्रहण के क्रम में यह आवश्यक होता है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही मापदंड अपनाया जाए जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके।

विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति-व्यक्ति आय का योगदान (Contribution of National and Per Capita Income in Economic Development)

किसी भी राष्ट्र की सम्पन्नता अथवा विपन्नता वहाँ के लोगों की प्रति-व्यक्ति आय या संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों के आय के योग जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं के माध्यम से जाना जाता है । राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अन्दर रहनेवाले लोगों की उत्पादकता अथवा उनकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने-अपने तरीके से विकास की योजना बनाती है, जिसका लक्ष्य

राष्ट्र के उपलब्ध साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है । इसी तरह शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूँजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है । आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पाद तथा आय में वृद्धि की जाती है । वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं । अत: हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति-व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है । बिना उत्पाद को बढ़ाए लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है और न ही आर्थिक विकास हो सकता है ।

राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन-स्तर पर पड़ता है । राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति (Net Product) को कहते हैं । लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में अधिक श्रमिकों को लगाया जाए । इस प्रकार जैसे-जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे-वैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तथा उनका जीवन-स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर होगा । इस प्रकार प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकेगा । यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक (Index) में वृद्धि होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में अवश्य ही वृद्धि होगी ।

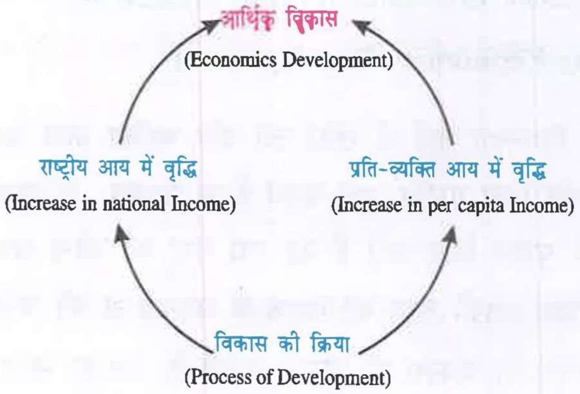

अबतक हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका जाता है अथवा जिनके लिए भुगतान किया जाता है, जिन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जाता उनकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती । उदाहरण- यदि कोई

नर्स (Nurse) अपने बच्चे की सेवा करती है तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होगी, लेकिन वही नर्स अस्पताल में काम करती है तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में की जाएगी। इस गणना के पश्चात् विकास की क्रिया सामान्य तौर पर चलती रहेगी ।

यदि विकास की क्रिया के तहत् राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो गरीबों द्वारा प्राप्त आय में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि बढ़ी हुई आय का सब हिस्सा अमीरों के पास चला जाएगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होते हुए भी संतुलित आर्थिक विकास नहीं होगा । इसी कारण इन दिनों सरकार के योजना आयोग के द्वारा समावेशी विकास (Inclusive Growth) पर बल दिया जा रहा है ।

जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो उसी अनुपात में या उससे अधिक अनुपात में यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो तो समाज का आर्थिक विकास नहीं बढ़ सकता । फिर भी इन परिस्थितियों के बावजूद यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के आर्थिक विकास में साधारण तौर पर वृद्धि देखी जा सकती है ।

समय एवं आय में परिवर्तन के साथ गरीबों की रुचि एवं स्वभाव परिष्कृत होता है तथा अपनी बढ़ी हुई आय का वे सदुपयोग करते हैं । इस प्रकार उनके आर्थिक विकास में अवश्य ही वृद्धि होती है । अत: हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि चंद परिस्थितियों को छोड़कर यदि राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो समाज के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी तथा राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय में कमी होने से समाज के आर्थिक विकास में भी कमी होगी।

सारांश :

- पूरे भारत में सबसे कम प्रति-व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है ।
- वर्तमान में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) के आँकलन में जहाँ कुल घरेलू उत्पाद (GDP) 2003-04 में नकारात्मक (Negative) - 5.15 प्रतिशत था वही 2004-05 से 2008-09 के बीच सकारात्मक (Positive) 11.03 प्रतिशत हो गया जो बिहार के विकास का अच्छा संकेत है ।
- राष्ट्रीय आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान्य आँकड़ा है । प्रत्येक देश में ऐसी संस्थाएँ हैं जो उस देश की आय के प्रमाणित आँकड़ों को प्रस्तुत करती है ।
- प्रति-व्यक्ति आय = किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात।
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था केंद्रिय सांख्यिकीय संगठन (CSO) है।
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक प्रयास में सर्वाधिक चर्चित उद्योगपति दादा भाई नैरोजी ने सन् 1967-68 में अपने आँकड़ों के अनुसार बतलाया कि भारत का प्रति-व्यक्ति आय सन् (1968) में 20 रुपये थी ।
- राष्ट्रीय आय के गणना के अनेक प्रयास किए गए किन्तु प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Dr. V.K. R.V. Rao के द्वारा सन् 1925-29 के बीच दिया गया आँकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था ।
- सकल घरेलू उत्पाद प्राय: एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है ।
- राष्ट्रीय आय की गणना के आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका है ।
- राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ– (i) आँकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, (ii) दोहरी गणना की संभावना, (iii) मूल्य मापने में कठिनाई ।
- विकास की क्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि से ही आर्थिक विकास की स्थिति सम्पन्न हो पाती है ।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Question)

I. सही विकल्प चुनें ।

1. सन् 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है ।

(क) 22,553 रुपये (ख) 25,494 रुपये

(ग) 6,610 रुपये (घ) 54,850 रुपये

2. भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है ?

(क) 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक (ख) 1 जुलाई से 30 जून तक

(ग) 1 अप्रैल से 31 मार्च तक (घ) 1 सितंबर से 31 अगस्त तक

3. भारत में किस राज्य का प्रति-व्यक्ति आय सर्वाधिक है ?

(क) बिहार (ख) पंजाब (ग) हरियाणा (घ) गोवा

4. बिहार के किस जिले का प्रति-व्यक्ति आय सर्वाधिक है ?

(क) पटना (ख) गया (ग) शिवहर (घ) नालंदा

5. उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है ।

(क) सहज (ख) वैज्ञानिक (ग) व्यवहारिक (घ) उपयुक्त तीनों

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ।

1. बिहार की ········ प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करती है।
2. उत्पादन, आय एवं ················ एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं ।
3. राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति-व्यक्ति आय में ············ होती है ।
4. राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि होने से ······ की क्रिया पूरी होती है ।
5. बिहार में वर्ष 2008-09 के बीच कुल घरेलू उत्पाद ······ प्रतिशत हो गया ।

III. सही एवं गलत कथन की पहचान करें ।

1. राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है।
2. उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है ।
3. भारत की प्रति-व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति-व्यक्ति आय से अधिक है ।
4. दादा भाई नैरोजी के अनुसार सन् 1968 में भारत की प्रति-व्यक्ति आय 20 रुपये थी ।
5. बिहार के प्रति-व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है ।

IV. संक्षिप्त रूप को पूरा करें-

(i) G.D.P.	(ii) P.C.I.	(iii) N.S.S.O.	(iv) C.S.O.
(v) G.N.P.	(vi) N.N.P.	(vii) N.I.	(viii) E.D.I.

V. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short-Answer Question)

1. आय से आप क्या समझते हैं ?
2. सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं ?
3. प्रति-व्यक्ति आय क्या है ?
4. भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी ?
5. भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है ?
6. राष्ट्रीय आय की गणना में होनेवाली कठिनाइयों का वर्णन करें ?
7. आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें?

VI. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long- Answer Questions)

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया ?
2. राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें । इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन-कौन सी है?

3. प्रति-व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें ?
4. राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें?
5. विकास में प्रति-व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें ?
6. क्या प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है वर्णन करें ?

VII. परियोजना कार्य (Project Work

1. छात्र चार्ट के माध्यम से अपने परिवार के आय के स्रोतों का वर्णन करें ?
2. कक्षा के छात्रों को दो समूहों में विभाजित करते हुए राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय के बारे में अपनी कक्षा में एक वाद-विवाद आयोजित करें ?
3. छात्र आप अपने परिवार की कुल मासिक आय एवं उस आय पर आश्रितों (परिवार के कुल सदस्यों) पर होने वाले खर्चों की एक सारणी बनाएँ ?

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर

I.	1. (ख)	2. (ग)	3. (घ)	4. (क)	5. (घ)
II.	1. 41.4	2. व्यय	3. वृद्धि	4. विकास	5. 11.03
III.	1. सही	2. गलत	3. गलत	4. सही	5. सही

*